इकाई 21 अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार

इकाई की रूपरेखा

21.0 उद्देश्य
21.1 प्रस्तावना
21.2 औपनिवेशिक शिक्षा
21.3 स्वदेशी शिक्षा
21.4 शिक्षा नीति संबंधी विवाद
21.5 अंग्रेज़ी शिक्षा का विकास
21.6 एक परिकलन
21.7 सारांश
21.8 शब्दावली
21.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

21.0 उद्देश्य

इस इकाई में 1757-1857 की अवधि में अंग्रेजी सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किये गये प्रयोगों से आपका परिचय कराया जायेगा। इस इकाई से आप सीख पायेंगे:

- उपनिवेशवाद एवं शिक्षा के बीच बदलते संबंध,
- स्वदेशी शिक्षा की विशेषताएं,
- शिक्षा नीति संबंधी विवाद,
- पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, तथा
- आधुनिक भारत में नई शिक्षा व्यवस्था का महत्व।

21.1 प्रस्तावना

भारत पर अंग्रेजी क्षेत्रीय प्रभुत्व की स्थापना के साथ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन हुए। शिक्षा उन क्षेत्रों में एक थी जिनमें अंग्रेजों द्वारा सत्ता अधिग्रहण के साथ अनेक परिवर्तन आये। ये परिवर्तन क्यों और कैसे आये, इनका प्रभाव क्या था? इस इकाई में इन्हीं कुछ प्रमुख प्रश्नों का विवेचन किया गया है।

21.2 औपनिवेशिक शिक्षा

औपनिवेशिक शासन के अधीन शैक्षिक विकास के बोध के लिए शिक्षा और उपनिवेशवाद के बीच गत्यात्मक संबंधों को समझना आवश्यक है। मार्टिन कार्नाय जैसे लेखकों का तर्क है कि औपनिवेशिक शासनाधीन देशों में शिक्षा का ढांचा औपनिवेशिक शासकों द्वारा अपने प्रभुत्व की वैधता तथा अपने आर्थिक हितों की सिद्धि के लिए रचा गया होता है। उपनिवेश देशों पर आर्थिक एवं राजनीतिक नियम औपनिवेशिक शासन की निरंतरता के लिए आवश्यक होता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। शिक्षा तंत्र के माध्यम से नये मूल्यों के विकास तथा औपनिवेशिक शासन का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है इस प्रकार शिक्षा प्रक्रिया अपनी स्वतंत्र

पहचान खो देती है और राजनीतिक नियंत्रण के अधीन आ जाती है।

औपनिवेशिक शिक्षा निस्संदेह उपनिवेशिक देशों में परिवर्तन तथा सांस्कृतिक रूपांतरण का सूत्रपात करती है। नये विचार तथा प्रयोग निश्चय ही वर्तमान ज्ञान की वृद्धि करते हैं। लेकिन औपनिवेशिक देशों को इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। औपनिवेशिक शिक्षा के वास्तविक लाभकर्ता थोड़े से ऐसे लोग होते हैं जिनको औपनिवेशिक शासन की निरंतरता बनाये रखने का दायित्व सौंपा गया होता है। औपनिवेशिक शिक्षा का अभीष्ट होता है उपनिवेशिक देशों पर बेहतर नियंत्रण, न कि उनका विकास। इस नीति का अंतिम परिणाम भिन्न हो सकता है, लेकिन वांछित उद्देश्य इसका होता है उपनिवेश देशों को नियंत्रण में रखना, न कि उनको बदलना।

औपनिवेशिक शासन तथा शिक्षा के बीच गतिशील संबंधों के बारे में अनेक इतिहासकारों के उपरोक्त विचार को ध्यान में रखते हुए हम भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा के विकास पर दृष्टिपात करेंगे। अंग्रेजी शिक्षा के आरंभ की चर्चा करने से पहले हम प्रारंभिक उन्नीसवीं सदी काल में स्वदेशी शिक्षा की स्थिति पर नजर डालेंगे।

21.3 स्वदेशी शिक्षा

आरंभिक ब्रिटिश दस्तावेजों से प्राप्त सूचनाओं से हमें 18वीं सदी के उत्तरार्द्ध एवं उन्नीसवीं सदी के आरंभ में स्वदेशी शिक्षा के बारे में बहुत स्थूल विचार ही मिल पाते हैं। उस समय मुस्लिम आबादी के लिए मदरसा और मकतबा तथा हिंदुओं के लिए टोल और पाठशालाएं होती थीं इस श्रेणीक्रम में अरबी तथा संस्कृत के उच्च अध्ययन केंद्रों से लेकर फारसी तथा स्थानीय भाषाओं में बुनियादी शिक्षा के लिए निचले दर्जे के संस्थान आते थे। वैज्ञानिक एवं धर्मनिरपेक्ष शिक्षण का अभाव उन दिनों में उच्च अध्ययन केंद्रों की प्रमुख सीमा थी। राजकाज की भाषा फारसी होने के कारण अनेक हिंदू भी फारसी स्कूलों में जाते थे और इन स्कूलों में हिंदू शिक्षक भी होते थे। टोल हो या मदरसा, स्वदेशी शिक्षा की कुछ सामान्य विशेषताएं थीं:

- स्कूलों का संचालन आमतौर पर जमींदारों अथवा स्थानीय धनी व्यक्तियों के योगदान से होता था।
- पाठ्यक्रम में संस्कृत, अरबी, फारसी भाषाओं तथा क्लासिकीय हिंदू इस्लामी परंपरा के विषयों, जैसे व्याकरण, तर्कशास्त्र, विधि, अध्यात्म, आयुर्विज्ञान पर बल दिया जाता था।
- यद्यपि संस्कृत शिक्षा ब्राह्मणों का ही विशेष क्षेत्र होता था, आरंभिक 19वीं सदी की उपलब्ध रिपोर्टों से हम पाते हैं कि इन स्कूलों में नीची जाति तथा अनुसूचित जाति के व्यक्ति भी स्थान पाते थे।
- महिलाएं आमतौर पर औपचारिक शिक्षा से अलग ही रखी जाती थीं।
- 19वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस के आने तक वाच्य परंपरा तथा अध्यापक की स्मरण शक्ति ही ज्ञान एवं सूचना का आधार बनती थी, जिनकी संपूरक हस्तलिखित पांडुलिपियां होती थीं।
- यद्यपि शासक विद्वता के लिए प्रसिद्ध व्यक्तियों को संरक्षण देते थे, शिक्षा में राज्य की भूमिका नगण्य अथवा शून्य ही होती थी।

उच्च जातियों के लिए बने उच्च शिक्षा केंद्रों के अतिरिक्त अनेकानेक प्राथमिक विद्यालय होते थे। इस प्रकार के प्राथमिक विद्यालय भारत के अधिकांश गांवों में थे। इनका संचालन गांव के जमींदार अथवा स्थानीय अभिजनों के आर्थिक अनुदान से होता था। ये विद्यालय विद्यार्थियों को बुनियादी गणित तथा दैनिक आवश्यकताओं का ज्ञान कराते थे। अत्यंत पिछड़ी प्रवंचित जातियों को छोड़कर समाज के विभिन्न तबकों से विद्यार्थी इन स्कूलों में आते थे।

इस प्रकार आरंभिक 19वीं सदी में भारत में विद्यमान शिक्षा प्रणाली की अपनी खूबियां थीं। प्राथमिक विद्यालय ग्रामीणों को बुनियादी शिक्षा का अवसर प्रदान करते थे। इनका पाठ्यक्रम दृष्टिकोण में धर्म निरपेक्ष तथा व्यावहारिक आवश्यकताओं के अनुरूप होता था। संभवत: उच्च शिक्षा केंद्रों (टोल तथा मदरसों) में व्याकरण, दर्शन एवं धर्म की सूक्ष्मताओं पर विशेष जोर से धर्म निरपेक्ष एवं वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार की संभावना क्षीण होती गई। उपनिवेशवादी शासकों ने स्वदेशी शिक्षा के स्थान पर अपनी शिक्षा व्यवस्था आरोपित की। व्यापक जनशिक्षा के साधन के रूप में स्वदेशी प्रणाली की संभावनाएं समाप्त की गई। अनुगामी खंड में हम भारत में शिक्षा के विकास में कंपनी की भूमिका के प्रसंग में विभिन्न गुटों के बीच उभरे विवादों की झलक देंगे।

4. पाठशाला का एक दृश्य

21.4 शिक्षा नीति संबंधी विवाद

ईस्ट इंडिया कंपनी को 18वीं सदी के उत्तरार्द्ध तक भारत में शिक्षा के संवर्धन में अपनी भूमिका के बारे में किसी दुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। मूलत: एक वाणिज्यिक निगम होने के कारण उसका बुनियादी लक्ष्य व्यापार तथा मुनाफों की लूट था। क्षेत्रीय सत्ता हथियाने से पहले कंपनी की कोई भूमिका शिक्षा कार्य में नहीं थी। मिशनरियों तथा अनुदान संचालित स्कूलों की स्थापना तथा विद्योपार्जन को प्रोत्साहन देने के प्रयास अवश्य हुए थे। लेकिन पूर्वी भारत पर ब्रिटिश अधिकार के साथ 18वीं सदी के उत्तरार्द्ध में चीजें बदलने लगीं। अधिकारी मंडलों के अंतर्गत तथा उसके बाहर शैक्षिक संवर्धन में कंपनी की संभाव्य भूमिका को लेकर विवाद उभरने लगा।

भारत में राजनीतिक सत्ता हथियाने के बाद कंपनी कर्मचारियों ने स्थानीय समाज के धर्म एवं संस्कृति जैसे क्षेत्रों में तटस्थता बरतने का ही प्रयास किया। इसका मुख्य कारण था स्थानीय जनता द्वारा प्रतिकूल क्रिया विरोध की आशंका। फिर भी, विभिन्न हलकों, मिशनरियों, उदारवादियों, प्राच्यविदों तथा उपयोगितावादियों से पड़ने वाले दबावों ने कंपनी को तटस्थता नीति छोड़ने और शैक्षिक संवर्धन का दायित्व उठाने के लिए बाध्य कर दिया। तीक्ष्ण मदभेदों को जन्म देने वाला दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था कि कंपनी पाश्चात्य अथवा प्राच्य शिक्षा को प्रोत्साहन दे। प्रारंभिक मंजिल पर कंपनी कर्मचारियों ने प्राच्य विद्या को प्रोत्साहन दिया। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कुछ अंग्रेज नागरिक प्राच्य विद्या को प्रोत्साहन देने की आकांक्षा रखते थे।

5. ओरियंटल शिक्षा पर एक कार्टून

इस संदर्भ में हम वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा (1781), जोनाथन डंकन द्वारा बनारस संस्कृत कालेज (1791) और विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल (1784) की स्थापना का उल्लेख कर सकते हैं। प्राच्य विद्या के वर्तमान संस्थानों को बनाये रखने तथा भारतीय क्लासिकीय परंपरा के संवर्धन के पक्षधर ओरियन्टलिस्ट कहलाए। उनका तर्क यह था कि भारतीयों में आमतौर पर यूरोपीय ज्ञान एवं विज्ञान के पूर्वाग्रह होने के कारण पाश्चात्य ज्ञान को पूरी तरह अस्वीकार किया जा सकता है यदि उसे क्लासिकीय भारतीय ज्ञान के माध्यम से न प्रस्तुत किया जाय। उनमें से कुछ की दिलचस्पी औपनिवेशिक समाज की क्लासिकीय परंपरा एवं संस्कृति के अवगाहन में थी। लेकिन यदि प्राच्य संस्कृति के संवर्धन की कतिपय अंग्रेज नागरिकों की सच्ची आकांक्षा को हम स्वीकार भी कर लें, तो भी यह मानना पड़ेगा कि ओरियंटलिस्ट कुछ व्यावहारिक उद्देश्यों से भी प्रेरित थे। वे अंग्रेज कर्मचारियों को स्थानीय भाषा एवं संस्कृति की शिक्षा देना चाहते थे ताकि वे अधिक कर्मकुशल बन सकें। 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स कालेज की स्थापना का यही मुख्य उद्देश्य था। दूसरा प्रेरक तत्व था स्थानीय समाज के अभिजनों से मित्र संबंधों का विकास और उनकी संस्कृति का बोध। कलकत्ता मदरसा तथा बनारस संस्कृत कालेज की स्थापना के पीछे यही मुख्य कारण था।

6. कलकत्ता मदरसा

Extracts from the Diary of H.T. Prinsep Concerning the Dispute between Orientalists and Anglicists

When the subject came underconsideration in Council, there was a very hot argument between myself and Mr. Macaulay. *The issue was the resolution that was published not abolishing existing colleges, but requiring them to teach English as well as native literature and making the former obligatory, also giving some encouragement to vernacular studies, but declaring that all Government pecuniary aid in future should be given exclusively to promote the study d European science through the medium of English Language. Lord W. Bentinck would not even allow my memorandum to be placed on record. He said it was quite an abuse that Secretaries should take upon themselves to write memorandums*: that it was enough for the Court of Directors to see what the Members of Council chose to place on record .... Thus ended this matter for the time. The Resolution passed on this occasion was modified afterwards and made a little more favourable for the old native institutions by Lord Auckland. *but English has ever since been the study preferentially encouraged by Government in connection with vernacular literature.* The study of Sanskrit. Arabic and Persian is. in consequence, less cultivated than heretofore. but none of the old institutions have been altogether abolished" (emphasis added).

Extracts from the Minute of the Hon'ble T.B. Macaulay, dated the 2nd February 1835

we now come to the gist of the matter. We have a fund to be employed as Government shall direct for the intellectual improvement of the people of this country. The simple question is, what is the most useful way of employing it?

All parties seem to be agreed on one pornr, that the dialects commonly spoken among the natives d this part d India contain nerther literary nor scientific information, and arc moreover so poor and rude that, until they are enriched from 'some other quarter, It will not be easy to translate any valuable work into them. It seems to be admitted on all sides, that the intellectual improvement d those classes d the people who have the means d pursuing higher studies can at persent be effected only by means d some language not vernacular amongst them.

What then shall that language be? One half of the committee maintain that it should be the English. The other half strongly recommend the Arabic and Sanscrit. *The whole question seems ro me to be— which language is the besr worth knowing?*

I have no knowledge of- either Sanscrit or Arabic. But I have done what I could to form a correct estimate of their value. I have read translations of the most celebrated Arabic and Sanscrit works. I have conversed. both here and at home. with men distinguished by their proficiency in the Eastern tongues. I am quite ready to take the oriental learning at the. valuation of the orientalists themselves. *I hare never found one among them who could deny that a single shelf d a good European library was worth the whole native literature d India and Arabia. The intrinsic superiority of the Western literature is indeedfully admitted by those members d the committee who support the oriental plan d education.*

इस ओरियंटलिस्ट दृष्टिकोण को इंग्लैंड में विभिन्न गुटों, इवैंजेलिकल, लिबरल तथा उपयोगितावादियों के विरोध का सामना करना पड़ा। औद्योगिक क्रांति के साथ इंग्लैंड में विकसित नये सांस्कृतिक आचार-विचारों में कंपनी की इजारेदारी नीति की आलोचना निहित थी। क्रांति के बाद के युग में आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति से पृथक कुछ भी मूल्यवान नहीं समझा जाता था। इवैंजेलिकलों का क्रिश्चियन विचारों तथा पाश्चात्य संस्थानों की श्रेष्ठता में दृढ़ विश्वास था। इवैंजेलिकल विचारों के दो प्रमुख प्रवर्तक थे, चार्ल्स ग्रांट और विलियम विल्बर फोर्स।

इवैंजेलिकल आस्थाओं में नहीं जुड़ने वाले अन्य व्यक्ति भी पाश्चात्य ज्ञान की श्रेष्ठता में विश्वास करते थे। इस विचार का एक प्रमुख पक्षधर था टामस बेविंगटन मैकाले। उसने इस बात पर बल दिया कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार-प्रसार ही भारत में शिक्षा नीति का उद्देश्य होना चाहिए।

भारत में उपयोगितावादी विचारों का मुख्य समर्थक जेम्स मिल भारतीय धर्म एवं संस्कृति का कटु आलोचक था। प्राच्य संस्थानों का पोषण कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है, ग्रांट तथा मैकाले के साथ उसका भी यही विचार था। उसका मुख्य जोर था वैज्ञानिक शिक्षण पर। लेकिन उसका मानना था कि भारत में वांछित परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है। इस उद्देश्य से वैधानिक एवं प्रशासनिक सुधार भी आवश्यक हैं।

संक्षेप में, विभिन्न गुटों की जिनकों आंग्लिसिस्ट कहा जा सकता है, आम धारणा यह थी कि भारतीय पिछड़ेपन की स्थिति में थे और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा ही इसका समाधान था, लेकिन यह शिक्षा व्यवसाध्य थी। इसलिए ऐसे जनसमूहों को शिक्षित करना आवश्यक था जो क्रमशः समूचे समाज को शिक्षित कर सकें (शिक्षा अभिजनों के स्तर से व्यापक जन समुदाय तक छनकर नीचे पहुंचेगी)। इस प्रकार यह भारत में नये सांस्कृतिक मूल्यों तथा ज्ञान के विकास में सहायक होगी। इस प्रस्ताव को परवर्तीकाल में Filteration Theory की संज्ञा दी गई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत को समर्थन देने का मिशनरियों का पूर्णतया भिन्न तर्क था। मिशनरियों का इरादा था शिक्षा के माध्यम से स्थानीय समाज तक पहुंचने का और नये सांस्कृतिक मूल्यों के प्रचार, का जो जनसमुदाय को ईसाई धर्म की ओर अधिकाधिक आकर्षित कर सकें।

शिक्षा नीति संबंधी इस विवाद पर भारतीयों की प्रतिक्रिया मिली-जुली थी राममोहन राय इत्यादि ने इस विश्वास के साथ पाश्चात्य शिक्षा का पक्षपोषण किया था कि इसकी सहायता से भारतीय पाश्चात्य विज्ञान, हेतुवाद, नये विचारों एवं साहित्य का अनुशीलन कर सकेंगे। इससे देश की पुनर्रचना में सहायता मिलेगी। कुछ अन्य लोगों का विश्वास था कि पाश्चात्य शिक्षा, विशेषकर अंग्रेज़ी ज्ञान, पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर शासक समुदाय के निकट आने में सहायक होगा। इसके विपरीत स्थिति थी परंपरावादियों की जो भारतीय भाषा एवं संस्कृति के घोर समर्थक थे। उनकी आशंका थी कि पाश्चात्य शिक्षा समाज तथा संस्कृति के विघटन की ओर ले जायेगी।

इस प्रकार, उपरोक्त विवेचन में हमें शिक्षा के विकास में कंपनी की भूमिका को लेकर भारतीयों तथा यूरोपीयों के बीच विभिन्न मत मतांतरों का पता चलता है। अगले भाग में हम **1757-1857** की अवधि में भारतीय शिक्षा में हुए प्रमुख विकासक्रम को देख पायेंगे।

बोध प्रश्न 1

1) 100 शब्दों में स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन करें।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

2) 50 शब्दों में पाश्चात्य अध्ययन के संवर्धन की ओर भारतीयों के रुझान के बारे में लिखें।

....

....

....

....

....

3) निम्न वाक्यों को पढ़ें और सही (✓) अथवा गलत (×) के चिह्न अंकित करें।

   i) स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक जनशिक्षा की उपेक्षा की गई।

   ii) स्वदेशी व्यवस्था में महिलाएं आमतौर पर शिक्षा से प्रवंचित थीं।

   iii) आरंभ में कंपनी कर्मचारियों ने स्वदेशी शिक्षा में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से अपने को अलग रखा।

   iv) ऑग्लिसिस्ट (Anglicists) पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहते थे, भारत को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से।

21.5 अंग्रेज़ी शिक्षा का विकास

जैसा कि आपने अभी देखा, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत उन्नीसवीं सदी के आरंभ में ही पाई जा सकती है। उसके पहले मिशनरियों अथवा कतिपय व्यक्तियों द्वारा किये गये प्रयासों की प्रकृति सीमित थी। इस संबंध में तंजोर, रामनाड तथा शिवगंगा के श्वार्त्स स्कूलों, सीरामपुर स्थित बाप्टिस्ट मिशनरियों, लंदन मिशन सोसाइटी, बंबई स्थित अमेरिकन मेथाडिस्ट्स इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में उनकी प्रवर्तक भूमिका थी। इन मिशनरी क्रियाकलापों और चार्ल्स ग्रांट व विलियम विल्बरफोर्स जैसे अंग्रेज नागरिकों के दबाव से कंपनी शिक्षा के क्षेत्र में पहल न करने की नीति छोड़ने को बाध्य हुई। पहली बार ब्रिटेन की संसद ने कंपनी के चार्टर में यह अनुच्छेद शामिल किया कि कौंसिल गवर्नर जनरल को प्रतिवर्ष कम से कम एक लाख रुपये शिक्षा के मद में रखने पड़ेंगे। लेकिन कंपनी ने इस कोष का इस्तेमाल मुख्यतः भारतीय भाषा एवं साहित्य के संवर्धन तथा प्रोत्साहन में ही किया। 1813 के चार्टर एक्ट का महत्व इस बात में है कि कंपनी ने पहली बार भारत में शैक्षिक संवर्धन संबंधी राजकीय दायित्व को मान्यता दी।

९. एक ब्राह्मण के साथ विलियम केरी

1823 में भारत में शिक्षा के विकास की देखरेख के लिए "जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन" (General Committee of Public Instruction) गठित की गई। इस कमेटी के अधिकांश सदस्य ओरियंटलिस्ट समूह के थे और उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा के बजाय प्राच्यविद्या को प्रोत्साहन देने का ही प्रबल समर्थन किया। फिर भी जैसा कि हम पिछले खंड में चर्चा कर चुके हैं, इंग्लैंड तथा भारत दोनों ही देशों में विभिन्न तबकों ने ब्रिटेन की संसद तथा कंपनी पर पाश्चात्य अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अधिकाधिक दबाव डाला। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के अध्यक्ष मैकाले तथा गवर्नर जनरल लार्ड बैंटिंक ने आंग्लिसिस्टों का पक्ष लिया। बैंटिंक ने आदेश जारी किया कि "अब से भारत में ब्रिटिश सरकार का एक प्रमुख लक्ष्य होगा यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का संवर्धन, और यह कि शिक्षा के लिए जुटाये गये कोष का सर्वोत्तम उपयोग अंग्रेज़ी शिक्षा के लिए ही हो सकता है।" बैंटिंक द्वारा 1835 में घोषित प्रस्ताव के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नांकित हैं:

- राजभाषा के रूप में फारसी का स्थान अंग्रेजी लेगी।
- अंग्रेजी पुस्तकों का मुद्रण तथा प्रकाशन निःशुल्क कर दिया जाएगा और उन्हें अपेक्षाकृत कम कीमत पर सुलभ बनाया जाएगा।
- अंग्रेज़ी शिक्षा के पोषण के लिए और अधिक कोष जुटाया जाएगा जबकि प्राच्यविद्या के लिए कोष में कटौती कर दी जाएगी।

बैंटिंक के बाद गवर्नर जनरल का पद संभालने वाले आकलैंड का भी विश्वास था, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता में। उसने ढाका, पटना, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली और बरेली में और कई अंग्रेजी कॉलेज खोलने की सिफारिश की। ज.क.प.इ. 1841 में खत्म कर दी गई और इसका स्थान कौंसिल ऑफ एजुकेशन ने लिया। इस कालखंड में अंग्रेजी शिक्षा के विकास का अगला प्रमुख प्रतीक चिह्न बना 1854 का "वुड डिस्पैच"। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड ने 1854 में उस नीति का निर्धारण किया जो भारत सरकार के शैक्षिक कार्यक्रम का निर्देशक सिद्धांत बनी। डिस्पैच में स्पष्ट रूप से घोषित किया गया था:

"भारत में जिस प्रकार की शिक्षा को व्यापक होते देखने की आकांक्षा हम रखते हैं, वह अपने यूरोप की परिष्कृत कलाओं, विज्ञान, दर्शन एवं साहित्य, संक्षेप में, यूरोपीय ज्ञान के प्रचार-प्रसार का उद्देश्य रखती है।" डिस्पैच की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थीं:

- कंपनी के अधीनस्थ पाँचों प्रान्तों में जन-अनुदेश के लिए एक विभाग का गठन किया जाएगा।
- कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- श्रेणीक्रमबद्ध विद्यालयों—उच्च, माध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों—का एक नेटवर्क बनाया जाएगा।
- अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी।
- स्थानीय शाखा के विद्यालयों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- विद्यालयों को आर्थिक सहायता देने के लिए अनुदान-व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी।

1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में तीन विश्वविद्यायों की स्थापना की गई। विश्वविद्यालयों की स्थापना और प्रांतों में शिक्षा विभागों की शुरुआत से भारत में आधुनिक शिक्षा को आधारभूत ढाँचा मिला। वास्तव में वुड डिस्पैच भारत में शिक्षा के अनुवर्ती विकास के लिए प्रतिरूप बन गया।

भारत में पाश्चात्य अध्ययन के विकास के लिए जब यह आधिकारिक पहल की गई, उसी अवधि में मिशनरियों तथा कुछेक व्यक्तियों द्वारा भी पाश्चात्य शिक्षा के संवर्धन के लिए आधिकारिक प्रयास किये गये थे। बंगाल के महत्वपूर्ण कॉलेजों में से कुछ की स्थापना ईसाई मिशनरियों ने की थी। इन मिशनरियों ने भारतीयों के बीच पाश्चात्य ज्ञान के प्रसार की आरंभिक मंज़िल पर प्रशंसनीय कार्य किया, यद्यपि उनका मूल उद्देश्य लोगों को ईसाई

धर्म की ओर आकर्षित करना था। मिशनरियों के अलावा कुछ व्यक्तियों ने कलकत्ता में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलकत्ता में स्कूलों की स्थापना करने तथा स्थानीय स्कूलों हेतु अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए नेटिव स्कूल एंड बुक सोसाइटी की स्थापना की गई। हिंदू (बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज नाम से प्रसिद्ध) कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में डेविड हेयर तथा कुछ महत्वपूर्ण हिंदू नागरिकों ने की, जिससे भारतीयों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का प्रचार-प्रसार सुगम हो गया। डेविड हेयर धार्मिक आस्थाओं तथा संस्कृत व अरबी भाषा-शिक्षण के विरुद्ध था। महिलाओं के परम समर्थक जे.इ.डी. बेथ्यून ने कलकत्ता में गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। विद्यासागर ने बंगाल में महिलाओं का समर्थन किया। इन सभी संस्थाओं को स्थानीय जनता की अनुकूल प्रतिक्रिया मिली, जिसने शैक्षिक अवसरों के और अधिक प्रसार के लिए अंग्रेजों से माँग की।

इस प्रकार बंबई और मद्रास में भी मिशनरी स्कूलों की स्थापना की गई। बंबई में नेटिव एजुकेशन सोसाइटी तथा एलफिंस्टन कॉलेज की स्थापना महत्वपूर्ण विकास था, जिसने कलकत्ता के हिंदू कॉलेज जैसी ही भूमिका निभाई। मद्रास में 1837 में क्रिश्चियन कॉलेज तथा 1853 में प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में पहले अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले कॉलेज की स्थापना 1853 में की गई। इस प्रकार 18वीं सदी के छठे दशक तक हम पाते हैं कि भारत के अधिकांश प्रांतों में आधुनिक शिक्षा की आधारशिला स्थापित कर दी गई थी।

21.6 एक परिकलन

उपरोक्त विवेचन से हमें अंग्रेजी शिक्षा के क्रमिक विकास का पता चलता है। सरकार ने 19वीं सदी में स्थानीय शिक्षा व्यवस्था की उपेक्षा करते हुए इस प्रणाली को प्रोत्साहन दिया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार एक सुदीर्घ प्रक्रिया थी और यह कई भिन्न चरणों से गुजरी। शिक्षा नीति को एक परिपक्व स्वरूप उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में मिला। फिर भी, 1857 तक शिक्षा में आये परिवर्तनों का निकट परीक्षण आवश्यक है। निस्संदेह, नई शिक्षा ने ज्ञान का क्षितिज व्यापक बनाया। विशेषकर प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना और पुस्तकों की सुलभता ने पारंपरिक बाधाओं को दूर करके अधिकाधिक लोगों के लिए शिक्षा को सुगम बनाया। पाश्चात्य चिंतकों के विचारों ने स्थानीय समाज की तरुण पीढ़ी को प्रभावित किया और वे वर्तमान पारंपरिक मूल्यों को प्रश्नाधीन बनाने लगे। हेतुवाद (Rationalism) की एक नई चेतना विकसित हुई। बहरहाल इस सकारात्मक प्रयास से भी अंग्रेजी शिक्षा की खामियों को खत्म नहीं किया जा सका।

अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था ने व्यापक जनशिक्षा के महत्व की पूरी तरह उपेक्षा की। स्वदेशी व्यवस्था के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से समाज के व्यापक तबकों को बुनियादी शिक्षा मिलती थी। लेकिन नई शिक्षा के अंतर्गत समूची जनता के बजाय कुछ गिने-चुने लोगों की ही शिक्षा पर बल दिया जाता था। अभिजनों के स्तर से जनसमुदाय तक शिक्षा के छनकर पहुँचने का विचार व्यावहारिक रूप नहीं ले सका। इस व्यवस्था ने सभी के लिए शिक्षा का समान अवसर नहीं दिया और सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों तथा समुदायों के पिछड़ेपन को बरकरार रखा। समाज में समुपस्थित विभाजन और व्यापक बन गया।

दूसरी बात यह थी कि पाश्चात्य विज्ञान एवं तकनीकी समर्थन के बावजूद स्कूलों-कॉलेजों के पाठ्यक्रम में पाश्चात्य साहित्य, दर्शन और मानविकी पर ही बल दिया जाता था। तकनीकी तथा प्राकृतिक विज्ञानों की उपेक्षा की गई और इस प्रकार के ज्ञान के बिना देश के बौद्धिक विकास के साथ-साथ आर्थिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। इस नई शिक्षा का दूसरा पहलू था – शिक्षा का राजनीतिक सत्ता के अधीनस्थ बन जाना। **ओरियंटलिस्ट** हों अथवा **आंग्लिसिस्ट** उनके द्वारा प्रस्तावित शिक्षानीति का बुनियादी उद्देश्य था – औपनिवेशिक शासन को सुदृढ़ बनाना। **ओरियंटलिस्ट** यह काम स्वदेशीकरण के माध्यम से और **आंग्लिसिस्ट** पश्चिमीकरण के माध्यम से करना चाहते थे। शिक्षानीति का बुनियादी उद्देश्य औपनिवेशिक शासन के राजनीतिक हितों से अलग नहीं हो सकता था।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सरकार की शिक्षानीति के भावी स्वरूप के बारे में व्यक्तियों तथा विचार-सारणियों के बीच भिन्नताएँ थीं। 19वीं सदी के पूर्वार्द्ध में शिक्षा नीति मतभेदों तथा विविध विचार-रूपों की उपज थी। समग्र रूप में, औपनिवेशिक प्रशासन अपने हितों की ही पुष्टि करने वाली शिक्षा नीति को प्रोत्साहन देने के लिए उत्सुक था।

बोध प्रश्न 2

1) 1835 और 1857 के बीच आधिकारिक शिक्षानीति का विवेचन करें। 100 शब्दों में उत्तर लिखें।

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

2) भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रभावों पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखें। उत्तर 100 शब्दों में दें।

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

21.7 सारांश

इस इकाई में हमने देखा है, कि प्रकार अंग्रेजों ने स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था के स्थान पर नई शिक्षा को आरोपित किया। अनेक अंग्रेज नागरिक ऐसे थे जिन्होंने प्राच्यविद्या को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया क्योंकि उनके विचार में पाश्चात्य शिक्षा स्थानीय समाज में विविध प्रतिक्रियाओं को जन्म दे सकती थी फिर भी पाश्चात्य अध्ययन के संवर्धन के लिए नये स्कूलों-कॉलेजों की स्थापना की गई। इस पाश्चात्य शिक्षा के फलस्वरूप अनुसंधान की एक नई चेतना का विकास हुआ। लेकिन इस शिक्षा नीति ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा की उपेक्षा की और इसके वास्तविक लाभकर्ता उच्चवर्गीय व्यक्ति ही थे। इस प्रकार अंग्रेजी शिक्षा के साथ आने वाला परिवर्तन बहुत सीमित प्रकृति का था।

21.8 शब्दावली

आंग्लिसिस्ट: भारत में पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर कंपनी कर्मचारी।

इवैंजेलिकल: इंग्लैंड में प्रोटेस्टैंट ईसाइयों का समुदाय जो ईसा मसीह तथा व्यक्तिगत प्रयासों की श्रेष्ठता पर विश्वास करता था। वे मानवीय प्रगति को ईसा मसीह तथा ईसाई संस्कृति में आस्था के माध्यम से ही संभव मानते थे।

उदारवादी (लिबरल): 19वीं सदी इंग्लैंड में एक नया राजनीतिक दल, लिबरल पार्टी के नाम से उभरा। इस पार्टी के सदस्य उदारवादिता में विश्वास करते थे और विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते थे।

ओरिंटलिस्ट: भारतीय संस्कृति, परंपरा और भाषाओं के संवर्धन के पक्षधर।

21.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) आपका उत्तर स्वदे [illegible] शिक्षा व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं, उसकी खामियों और खूबियों पर केन्द्रि [illegible] होना चाहिए। देखें भाग 21.3
2) प्रतिक्रिया का स्वरूप मिला-जुला था, कुछ ने पाश्चात्य शिक्षा का पक्ष लिया, कुछ उसके आलोचक थे। देखें भाग 21.4
3) i) ✗ ii) ✓ iii) ✓ iv) ✗

बोध प्रश्न 2

1) आपके उत्तर में बैंटिंक प्रस्ताव, आकलैंड नीति तथा वुड डिस्पैच शामिल होने चाहिए।
2) आपको अंग्रेज़ी शिक्षा के सकारात्मक योगदान का एक मूल्यांकन करना है और उसकी सीमाओं का उल्लेख करना है। देखें भाग 21.6